The ESIC and the Ministry say that Orissa Government is not giving 25 acres of land which is required for the medical college. Whether Orissa Government is really not giving the land or the ESIC is not interested in having a medical college in Orissa, we do not know. But, Orissa State, as a whole, is losing a medical college proposed by the ESIC.

I, therefore, urge upon the Labour Ministry to discuss with the Orissa Government to get the required land for medical college or the ESIC may also directly purchase 25 acres of land and start a medical college or else Orissa people and ESIC personnel may start agitation programme to press for their right for having a medical college and a dental college of ESIC in Bhubaneshwar, Orissa.

Demand for linguistic minority Status to Nepali speaking people in the country

श्री समन पाठक (पश्चिमी बंगाल) : महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान नेपाली/गोरखी भाषा-भाषियों को भाषायी अल्पसंख्यक दर्जा दिए जाने की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा।

महोदय, नेपाली भाषा देश के हर क्षेत्र में बोली जाती है। यह भाषा बोलने और समझने वालों की अनुमानित जनसंख्या एक करोड़ से ज्यादा है। नेपाली भाषा बोलने वाले विशेष रूप से दार्जिलिंग एवं पश्चिमी बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों से लगे सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, दिल्ली, मुम्बई, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एवं दक्षिण भारत के कुछ हिस्से में निवास करते हैं।

महोदय, किसी भी जाति का चिह्न उनकी भाषा एवं भूमि से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन हिन्दी भाषा और उर्दू भाषा भारत के हर क्षेत्र में बोली जाती है। उनको एक निश्चित प्रदेश की भाषा के रूप में नहीं जाना जाता है। वैसे ही नेपाली भाषा भी किसी एक प्रदेश की निश्चित भाषा नहीं है। वह देश के हर प्रांत में बोली जाती है। लेकिन हिन्दी एवं उर्दू की तरह नेपाली भाषा विकसित नहीं हो पाई है, क्योंकि हर राज्य/प्रदेश में यह भाषा क्षेत्रीय भाषा या अल्पसंख्यक भाषा के रूप में है। 1992 में नेपाली भाषा का आठवीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त होने के बाद भी इसका आशानुरूप विकास नहीं हो रहा है।

महोदय, भारतवर्ष विभिन्न भाषा, साहित्य-संस्कृति एवं परम्परा मिश्रित देश है। यह विभिन्नता में एकता एवं अखंडता का बेमिसाल नमूना है। अगर नेपाली/गोरखी भाषा और भी सम्बद्ध एवं विकसित हुए, तो यह देश के मिश्रित भाषा, साहित्य-संस्कृति धरातल को और मजबूत करने में मददगार साबित होगा।

अत: मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह नेपाली भाषा-भाषियों को हर राज्य/प्रदेश में भाषायी अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान करने में मदद करे।

Need to protect the fossils and cave paintings from Mining Mafia and smugglers in Sonbhadra District, Uttar Pradesh

श्री कलराज मिश्र (उत्तर प्रदेश) : मान्यवर, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में सलखन पार्क में 150 करोड़ वर्ष पुराने फासिल्स का रख-रखाव, संरक्षण करने में लापरवाही बरती जा रही है। इस स्थल की जानकारी वैज्ञानिक मैकलेनन ने 1831 में दुनिया को दी, लेकिन उसके 112 साल बाद 1993 में जे. वी. आर्डन ने सलखन आकर अध्ययन से यह साबित किया कि अमेरिका के यलो स्टोन नैशनल पार्क से भी फासिल्स का बेहतर उदाहरण यहां मौजूद है। जबकि सोनभद्र में ही एक और जटाशंकर फासिल्स पार्क के अस्तित्व ने पृथ्वी पर जीवन के प्रारंभ के प्रमाण उपलब्ध कराए।

5 दिसम्बर, 2002 को जब विश्वविख्यात भू-वैज्ञानिक एवं मैकनिल यूनिवर्सिटी कनाडा के एच. जे. हाफमैन यहां पहुंचे तो 150 करोड़ वर्ष पुराने फासिल्स को देखकर अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करने से नहीं रोक सके। उन्होंने नाचते हुए कहा, " पूरे विश्व में इससे खूबसूरत और स्पष्ट फासिल्स और कहीं है ही नहीं।" अमेरिका से आई दो महिला वैज्ञानिकों ने माना था, सलखन के फासिल्स 150 करोड़ वर्ष पुराने व परिपक्व हैं. जबकि यलो स्टोन अमेरिका के फासिल्स अभी निर्माण प्रक्रिया में हैं।

वर्ष 2002 में फासिल्स पार्क को धरोहर का दर्जा दिया गया है। स्थानीय प्रशासन की लापरवाही की वजह से मूर्ति तस्कर और पत्थर माफियाओं की नजर इस पार्क पर है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इसे धरोहर घोषित करने का कोई मायने नहीं रह गया है। यहां के स्थानीय लोगों ने राज्यपाल, राज्य सरकार ही नहीं, केन्द्र सरकार को भी कई बार ज्ञापन भेजे हैं, और चिट्ठियां थमाई हैं, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई।

मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि 150 करोड़ वर्ष पुराना फासिल्स व हजारों वर्ष पूर्व आदि मानव द्वारा पहाड़ियों पर बनाए गए चित्रों को खनन माफियाओं व मूर्ति तस्करों से बचाएं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The House is adjourned to meet tomorrow at 11.a.m.

The House then adjourned at ten minutes past seven of the clock till
eleven of the clock on Friday, the 7th August, 2009.